भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 523 का उत्तर

शहडोल में रेल परियोजनाएँ

523. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहडोल लोक सभा क्षेत्र से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं (जैसे नई लाइनें, दोहरीकरण या विद्युतीकरण) की वर्तमान स्थिति और उनकी संशोधित पूर्णता समय-सीमा क्या है;

(ख) क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों (जैसे शहडोल, अनूपपुर या उमरिया) पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें शुरू करने या नई इंटरसिटी/एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहडोल क्षेत्र, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रेल संपर्क और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा सिग्नलिंग में सुधार और मानवरहित क्रॉसिंग हटाने जैसी कोई विशेष पहल की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या क्षेत्र में माल परिवहन (कोयला, वनोपज आदि) को अधिक कुशल बनाने और रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए कोई नया मालढुलाई गलियारा या टर्मिनल सुविधा विकसित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): हाल ही के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट

आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹ 632 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹14,745 करोड़ (23 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-25 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	145 कि.मी.	29 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	2651 कि.मी.	241 कि.मी. प्रति वर्ष (8 गुना से अधिक)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली ₹89,543 करोड़ रूपए लागत की 4,740 कि.मी. कुल लंबाई की 24 रेल परियोजनाएं (08 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं, जिनमें से 2092 कि.मी. लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2025 तक 41,401 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रू. में)
नई लाइनें	8	1,914	544	15,069
आमान परिवर्तन	2	809	430	6,766
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	14	2,017	1,118	19,566
कुल	24	4,740	2,092	41,401

शहडोल सहित मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रू. में)
1.	अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन (165 कि.मी.) (शहडोल निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है)	2,311
2.	पेन्ड्रा रोड-अनूपपुर तीसरी लाइन (50 कि.मी.) (शहडोल निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती हुई)	394
3.	बिलासपुर में सड़क ऊपरी पुल (72 कि.मी.) सहित खोडरी-अनूपपुर दोहरीकरण (शहडोल निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है)	792
4.	भोपाल-बीना तीसरी लाइन (145 कि.मी.)	1,075
5.	बीना-कोटा दोहरीकरण (283 कि.मी.)	2,477
6.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया आमान परिवर्तन (300 कि.मी.)	2,005
7.	छिंदवाड़ा-नागपुर आमान परिवर्तन (150 कि.मी.)	1,512
8.	छिंदवाड़ा-मंडला फॉर्ट आमान परिवर्तन (182 कि.मी.)	1,268
9.	घाट पिंडारी-बलखेड़ा दोहरीकरण (6 कि.मी.)	29
10.	गुना-रूठियाई दोहरीकरण (20 कि.मी.)	175
11.	कटनी यार्ड से होकर गुजरने वाली झुकेई कॉर्ड लाइन (2 कि.मी.)	12
12.	सोनतलाई-बागरातवा दोहरीकरण (7 कि.मी.)	110
13.	इटारसी-बुधनी तीसरी लाइन (25 कि.मी.)	286
14.	तीगांव-चिचोंडा घाट खंड तीसरी लाइन (17 कि.मी.)	176
15.	बरखेड़ा-भोपाल तीसरी लाइन (41 कि.मी.)	473

16.	गंभीर पुल का नागदा-उज्जैन दोहरीकरण (2 कि.मी.)	28
17.	नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण (56 कि.मी.)	560
18.	बुधनी-बरखेड़ा तीसरी लाइन (27 कि.मी.)	1,703
19.	इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण (79 कि.मी.)	757
20.	पावरखेड़ा-जुझारपुर रेल ऊपरी पुल (16 कि.मी.)	443
21.	गुना-इटावा नई लाइन (348 कि.मी.)	683
22.	रमना-सिंगरौली दोहरीकरण (160 कि.मी.)	2,436
23.	करैला रोड-शक्तिनगर दोहरीकरण (32 कि.मी.)	763
24.	मालखेड़ी-महादेवखेड़ी दोहरीकरण (12 कि.मी.)	59

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली और शुरू की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रू. में)
1.	शहडोल-सिंहपुर चौथी लाइन (6 कि.मी.) (शहडोल निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है)	54
2.	कटनी - ग्रेड सेपरेटर/बाईपास (35 कि.मी.)	2,300
3.	कटनी - सिंगरौली दोहरीकरण (257 कि.मी.)	4,377
4.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो नई लाइन (541 कि.मी.)	8,914
5.	रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन (277 कि.मी.)	5,073
6.	इंदौर-बुधनी नई लाइन (198 कि.मी.)	7,474
7.	नीमच-बड़ी सादड़ी नई लाइन (48 कि.मी.)	495
8.	कोटा तक विस्तार के साथ ग्वालियर-श्योपुर कलाँ आमान	2,913

	परिवर्तन (284 कि.मी.)	
9.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन (280 कि.मी.)	2,450
10.	झांसी-बीना तीसरी लाइन (153 कि.मी.)	2,002
11.	मथुरा-ग्वालियर-झांसी तीसरी लाइन (274 कि.मी.)	5,924
12.	कटनी-बीना तीसरी लाइन (260 कि.मी.)	3,138
13.	सतना-रीवा दोहरीकरण (50 कि.मी.)	590
14.	रूठियाई बाईपास लाइन (3 कि.मी.)	54
15.	गुना बाईपास लाइन (2 कि.मी.)	179
16.	उज्जैन फ्लाई ओवर (2 कि.मी.)	100
17.	इंदौर-मनमाड नई लाइन (360 कि.मी.)	18,529
18.	भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 कि.मी.)	3,285
19.	दाहोद-इंदौर नई लाइन (205 कि.मी.)	9,746
20.	नीमच-रतलाम दोहरीकरण (133 कि.मी.)	1,096
21.	छोटा उदेपुर-धार नई लाइन (147 कि.मी.)	1,794
22.	रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन (41 कि.मी.)	964
23.	वड़ोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन (259 कि.मी.)	8,387
24.	रतलाम-खंडवा आमान परिवर्तन (299 कि.मी.)	7,265
25.	बीना-इटारसी चौथी लाइन (237 कि.मी.)	4,329
26.	इटारसी-नागपुर चौथी लाइन (297 कि.मी.)	5,010

पिछले तीन वर्षों, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 5,901 कि.मी. लंबाई के 61 सर्वेक्षणों (18 नई लाइन और 43 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य में संपर्कता में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)
1.	पेन्ड्रा रोड-शहडोल-कटनी चौथी लाइन (शहडोल निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है)	201
2.	नीमच-दाहोद-नंदुरबार नई लाइन	380
3.	रतलाम बाईपास लाइन	24
4.	कटनी-मानिकपुर तीसरी लाइन	176
5.	डॉ. अंबेडकर नगर (इंदौर)- खंडवा दोहरीकरण	112
6.	नागदा-भोपाल तीसरी और चौथी लाइन	240
7.	कटनी-इटारसी तीसरी लाइन	336
8.	कटनी-सिंगरौली तीसरी और चौथी लाइन	251
9.	नागदा जंक्शन-रामगंजमंडी जंक्शन तीसरी और चौथी लाइन	153
10.	खंडवा-इटारसी तीसरी और चौथी लाइन	187

भारतीय रेल पर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, लगभग 99.1% बड़ी आमान नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष नेटवर्क पर विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किया गया विद्युतीकरण कार्य निम्नानुसार है:

अवधि	मार्ग (किलोमीटर)
2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष)	21,801
2014-25	46,900

मध्य प्रदेश में शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र समेत समस्त मौजूदा बड़ी आमान नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को विद्युतीकरण के साथ स्वीकृत एवं निर्मित किया जा रहा है।

किसी मार्ग/खंड में वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाओं सहित नई रेलगाड़ियों को शुरू करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नानुसार शामिल हैं:

- उस खंड की क्षमता
- रेलपथ की उपलब्धता
- आवश्यक चल स्टॉक की उपलब्धता
- चल स्टॉक के अनुकूल अवसंरचना की उपलब्धता।
- रेलपथों और अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की आवश्यकता।

तदनुसार, वर्तमान में शहडोल, अनूपपुर और उमरिया स्टेशनों के यात्रियों की आवश्यकताओं को क्रमशः 70 गाड़ी सेवाओं, 74 गाड़ी सेवाओं और 46 गाड़ी सेवाओं द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर वंदे भारत गाड़ी सेवा सहित रेलगाड़ी सेवा को शुरू करना परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य, प्रतिस्पर्धी मांगों आदि के अध्यधीन एक सतत प्रक्रिया है।

खंड की क्षमता बढ़ाने के लिए, अनूपपुर-शहडोल-उमरिया-कटनी खंड (166 मार्ग कि.मी.) के लिए स्वचालित सिगनल प्रणाली के कार्य को मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, संरक्षा को बढ़ाने के लिए, अनूपपुर-शहडोल-उमरिया-कटनी खंड में कवच के कार्य को मंज़ूरी दी गई है।

मध्य प्रदेश में शहडोल सहित भारतीय रेल के बड़ी आमान नेटवर्क की चालू लाइनों पर सभी बिना चौकीदार वाले समपार फाटकों को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है।

शहडोल के निकट अर्थात् घुंघूटी और अमलाई रेलवे स्टेशनों पर जीसीटी के प्रस्ताव को बिलासपुर मंडल द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नानुसार शामिल हैं:-

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी स्वीकृति**
- **अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति**
- **परियोजना स्थल विशेष आदि के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

******